

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-श्री बलदेवसिंह हाडा

निगरानी संख्या 27/14

तारीख रजू- 27/11/2014

शंकर लाल पुत्र काना जाति माली निवासी छोटा बाजार चौथ का बरवाडा।

निगरानीगुजार

बनाम
- तुलसीराम पुत्र काना जाति माली पेशा सरकारी नोकरी(अध्यापक) निवासी छोटा बाजार चौथ का बरवाडा।

- ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा।

निर्णय

विपक्षीगण

दिनांक- 14/09/15

निगरानीगुजार ने यह निगरानी राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 19/03/85 के विरुद्ध पेश की है जिसमें ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को 16.5 X 46 वर्गफुट यानी 759 वर्गफुट पर नजराना 90 पैसे से लिया जाकर खाम से पुख्ता निर्माण की इजाजत दी गई है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। विपक्षी संख्या 1 व 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर इस उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीगुजार के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि काना के दो लडके शंकरलाल व तुलसीराम थे। विपक्षी तुलसीराम पढा लिखा था। काना की मृत्यु के समय शंकरलाल नाबालिग था। निगरानीगुजार कृषि में सभालता था तथा तुलसीराम नौकरी करता था। तुलसीराम ने पंचायत में पट्टा बनाने के लिए पत्र पेश किया उस समय निगरानीगुजार की उम्र 10 वर्ष के लगभग थी। वह नाबालिग था जबकि पंचायत के स्वामित्व के भू-खण्ड का पट्टा पंचायत ने विपक्षी को बिना किसी तरह की जाँच कराये जारी कर दिया जबकि विपक्षी ने अपने आवेदन में भू-खण्ड को पुश्तेनी होना बताया था क्योंकि निगरानीगुजार नाबालिग था इसलिये पंचायत के समक्ष आपत्ति पेश नहीं कर सका। उक्त पट्टा पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 267 के तहत जारी किया है। वर्तमान पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत रिवीजन पेश की गई है। अतः निगरानीगुजार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का निर्णय/जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

निगरानीगुजार के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील विपक्षी ने बहस में तर्क दिया कि निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है। काना के दो भाई घासी व काना थे। काना के लडके शंकरलाल व तुलसीराम हुए लेकिन घासीलाल ने शंकरलाल को गोद ले लिया था जबकि काना की सम्पत्ति तुलसीराम के हिस्से में आयी है। निगरानी में 10/10/14 को निर्णय की जानकारी होना पचा है जबकि उसके भी 5 माह बाद निगरानी पेश की है। निगरानीगुजार 30 वर्ष पुराने पट्टे को निरस्त करना चाहता है उन्होंने बताया कि उक्त पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता सिविल न्यायालय ही पट्टे को निरस्त कर सकता है व उन्होंने WLC(UC)1999 P-264 की नजीर पेश की है। विद्वान वकील विपक्षी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि निगरानीगुजार ने तुलसीराम का दिनांक 11/07/2001 का पत्र पेश किया है जिसमें तुलसीराम ने अपना 1/2 हिस्सा मकान में होने का कथन किया है। यह बात सही मानली जावे तो भी यह जाहिर है कि निगरानीगुजार को इस बात की जानकारी थी कि तुलसीराम ने पट्टा बना लिया है उसे उसी समय निगरानी/अपील करनी चाहिये थी इतने वर्षों बाद निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः निगरानीगुजार की निगरानी खरिज फरमाई जाकर ग्राम पंचायत का निर्णय/जारी पट्टा यथावत रखा जावे।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

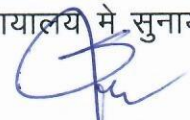
निगरानी संख्या 27/14 शंकरलाल बनाम तुलसीराम

बहस के जवाब में विद्वान निगरानीगुजार ने बताया कि कृषि भूमि के नामान्तरकरण घासी व काना दोनो के दोनो भाईयो व मों के नाम खुले हैं। सन् 2001 के शपथपत्र से भी यह जाहिर है कि तुलसीराम ने निगरानीगुजार का 1/2 हिस्सा होना माना है। ग्राम पंचायत ने मोके की जॉच निष्पक्ष नहीं करायी है अन्यथा दोनो भाईयो की संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति थी। तुलसीराम ने अपने आवेदन में भी पुश्तैनी सम्पत्ति होना माना है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

दोनों विद्वान अभिभाषको की बहस को गोर किया। निगरानी में दिनांक 06/05/14 को जानकारी पंचायत के आदेश की होना अंकित किया है लेकिन निगरानी 10/10/14 को पेश की है। मियाद कानून की धारा 5 के तहत आवेदन में कोई ठोस कारण नहीं दिया है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जो आदेश पारित किया है उसके बारे में उठाई गई आपत्तियां व तथ्यों से विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया है। अतः निगरानी मियाद अन्दर शुमार की जाती है। निगरानीगुजार व विपक्षी संख्या 1 दोनों सगे भाई हैं उनके पिता काना एवं घासी सगे भाई थे। दोनों कि विरासत निगरानीगुजार शंकरलाल व तुलसीराम तथा उनकी माता के नाम पर कृषि भूमि का नामान्तरकरण से तय हुई है इससे भी जाहिर है कि दोनों भाईयो का खाम मकान में हिस्सा है। विपक्षी ने शंकरलाल के गोद जाने का जो तर्क दिया है लेकिन उस बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। उक्त पटटा जारी हुआ उस समय निगरानीगुजार ने अशक्य होने का तर्क किया है इस बारे में विपक्षी का कोई खण्डन नहीं आया है। तुलसीराम की ओर से 2001 के स्टाम्प पर लिखावट से भी मकान में 1/2 हिस्सा होने के बारे में उसकी घोषणा से पंचायत के पटटे के बारे में संदेह उपजते हैं।

अतः सम्पूर्ण तथ्यों को देखते हुए पंचायत द्वारा मोके पर जॉच सही ढंग से कराये बिना गलत तथ्यों के आधार पर पटटा जारी किया है। कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं ली है। अतः ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा का आदेश दिनांक 19/03/85 व निर्णय की पालना में जारी पटटा दिनांक 19/03/85 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करने हेतु ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर